

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtrdoot.com

जालोर

Rashtrdoot

फोन:- 226422, 226423 फैक्स:- 02973-226424

वर्ष: 21

संख्या: 65

प्रभात

जालोर, शुक्रवार 12 जून, 2026

पो. रजि. /R/J/SRO/9640/2022-24

पृष्ठ 6

मूल्य 2.50 रु.

राहुल तथा सोनिया से मिले ममता एवं अभिषेक

अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी के सामने ममता बनर्जी को राज्यसभा में भेजने और सदन में विपक्ष का नेता बनाने का विकल्प पेश किया

-श्रीनंद झा-

राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो- नई दिल्ली, 11 जून। क्या ममता बनर्जी राज्यसभा में प्रवेश करेंगी और इसके बाद कांग्रेस की मदद से सदन में विपक्षी नेता के पद तक पहुँच जाएँगी? ऐसी संभावनाओं पर दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच चर्चा चल रही है।

- इसी बीच खबर है कि तृणमूल के बागी गुट से तकरिबन आधा दर्जन सांसद पुनः ममता बनर्जी के पक्ष में आ गए हैं।
- अगर ऐसा होता है तो बागी गुट के पास दो तिहाई से कम सांसद रह जायेंगे जो दलबदल कानून के तहत अलग गुट के रूप में मान्यता दिए जाने के लिए आवश्यक है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ हुई अपनी बैठक में प्रस्तुत किया था। ममता खुद एक दिन पहले सोनिया गांधी से मिली थीं। कहा जाता है कि कांग्रेस नेतृत्व इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।

समर्थक मान रहा था, ने अलग हुए समूह से दूरी बना ली है। इसके अलावा, लगभग आधा दर्जन सांसदों को पार्टी में वापसी की भी रिपोर्टें हैं। यदि ऐसा होता है, तो विद्रोही समूह के पास आवश्यक दो-तिहाई बहुमत से काफी कम समर्थन रह जाएगा, जैसा कि दल-बदल विरोधी कानून में प्रावधान है।

सुधिता देब शामिल हैं, जिससे राज्यसभा में टीएमसी सदस्यों की संख्या घट कर 11 रह गई है। इधर पता चला है कि पार्टी के लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी, जिन्हें ममता का नजदीकी सहयोगी माना जाता है, ने भी टीएमसी सुप्रीमो को अल्टीमेटम दिया है: "मुझे चुनें या अभिषेक बनर्जी को।" कल्याण ने गुरुवार को अभिषेक की आलोचना करते हुए, सार्वजनिक रूप से कहा कि ममता के भतीजे और पार्टी के महासचिव "अहंकारी" हैं और "सोचते हैं कि सभी उनके नीचे हैं।"

म.प्र. से भाजपा ने राज्यसभा की तीनों सीटें जीती

भोपाल, 11 जून। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने जीत ली हैं। पार्टी के तीनों उम्मीदवारों तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को गुरुवार को निर्बिरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया।

राज्यसभा निर्वाचन के तय

- नाम वापसी का समय समाप्त होने के बाद भाजपा प्रत्याशियों को निर्बिरोध निर्वाचित घोषित कर दिया व सर्टिफिकेट भी दे दिए गए।

कार्यक्रम के अनुसार, उम्मीदवारी से नाम वापसी का गुरुवार को अंतिम दिन था। दोपहर 3 बजे नाम वापसी का समय समाप्त होने के बाद भाजपा के तीन उम्मीदवारों को निर्बिरोध विजयी घोषित (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अभिषेक बनर्जी प.बंगाल सीआईडी के सामने पेश हुए

इससे पहले अभिषेक को तीन बार सीआईडी ने बुलाया था पर वे नहीं गए थे

-अंजन राय-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 जून। विधानसभा सदस्यों के हस्ताक्षरों की कथित जालसाजी के मामले में तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी आज पश्चिम बंगाल सीआईडी के सामने पेश हुए। इससे पहले वे तीन बार सीआईडी के सामने पेश होने से बच चुके हैं।

- सीआईडी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अभिषेक ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए स्वीकर को जो पत्र लिखा था उसमें कितने विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर थे तीन विधायकों ने तो दावा किया है कि पत्र पर उनके साइन नहीं हैं।

- अगर यह आरोप साबित हो गया तो अभिषेक को सात साल की जेल हो सकती है।

- विधानसभा चुनाव हारने के बाद हालात बदल गए हैं। ममता बनर्जी को भाव नहीं मिल रहा है, कई नेता उनका फोन तक नहीं उठा रहे हैं।

- ममता जी भी बेहद शांत हो गई हैं पूर्व में दिल्ली से लौटने पर वे गंभीर टिप्पणियां करती थीं पर इस बार वे एयरपोर्ट से चुपचाप निकल गईं।

दिल्ली में कुछ दिन बिताने के बाद, वे कोलकाता लौटे और वहां से उन्हें राज्य की सबसे चर्चित जांच एजेंसी के समक्ष पेशी के लिए ले जाया गया।

पुलिस की जांच शाखा यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या विपक्ष के नेता के नाम का प्रस्ताव भेजने से पहले उन्होंने वास्तव में 70 विधायकों की सहमति ली थी। तीन

विधायक पहले ही कह चुके हैं कि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली में बादल छाये, भीषण गर्मी से राहत

दो दिन तेज आंधी, बारिश की संभावना

नई दिल्ली, 11 जून। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार को मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। सुबह से ही आसमान में काले घने बादल छा गए और कई इलाकों में तेज हवा चलने लगी। कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी भी देखने को मिली। इस बदलाव से भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को राहत का अहसास हुआ।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने राजधानी और आसपास के क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए आगे कुछ घंटों में तेज आंधी, गरज चमक के साथ बारिश और 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफतार से हवा चलने की संभावना जताई है।

आईएमडी के मुताबिक, 12 जून को आंधी और बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। बारिश और हवा के असर से तापमान में 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज हो सकती है। अनुमान है कि अधिकतम तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा।

'कर्नाटक के मुख्यमंत्री का महा कचरा घोटाला'

भाजपा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर कचरा प्रबंधन में 39,000 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया

-जाल खंबाता-

राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो- नई दिल्ली, 11 जून। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गुरुवार को कर्नाटक में कांग्रेस सरकार, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार कर रहे हैं, पर एक कचरा प्रबंधन प्रोजेक्ट के माध्यम से करदाताओं को भारी नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया।

- भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर लिखी एक पोस्ट में कहा कि कचरा प्रोसेस करने के लिए दी जाने वाली टिपिंग फीस 260 रुपये से बढ़ाकर 2400 रुपये कर दी गई है यानि 950 प्रतिशत वृद्धि। उन्होंने करदाताओं को भारी नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया।

एक्स पर की गई अपनी पोस्ट में पूनावाला ने इस प्रोजेक्ट को "महा कचरा घोटाला" बताया और इसे उन विवादों की श्रृंखला से जोड़ा, जिनमें भाजपा पहले भी कांग्रेस सरकार पर शामिल होने का आरोप लगाती रही है। उन्होंने लिखा, "कर्नाटक में बड़ा कचरा घोटाला! एमयूडीए घोटाला, ठेकेदार घोटाला,

आवास घोटाला, शराब घोटाला और भूमि घोटाला के बाद, अब कांग्रेस का 39,000 करोड़ रुपये का कचरा घोटाला सामने आया है।" पूनावाला के अनुसार, कचरा प्रसंस्करण (वेस्ट प्रोसेसिंग) के लिए दी जाने वाली टिपिंग फीस लगभग 260 रुपये प्रति टन से (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'आज रात ईरान पर सबसे बड़ा हमला'

वॉशिंगटन, 11 जून। पश्चिम एशिया में बड़े युद्ध का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार दूसरे दिन जोरदार हमले हुए हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमेरिका आज रात ही ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि बहुत जल्द अमेरिका ईरान के तेल और गैस उद्योग पर अपना पूरा कब्जा जमा लेगा। इसमें ईरान का सबसे मुख्य तेल केन्द्र खर्ग द्वीप भी शामिल है। दोनों देशों के बीच यह भीषण लड़ाई गुरुवार सुबह तक चलती रही। अमेरिकी सेना का यह हमला पिछले दिन के मुकाबले बहुत ज्यादा बड़ा, तेज और आक्रामक था। इस हमले से ईरान को काफी नुकसान पहुंचने की बात कही जा रही है। दूसरी तरफ, ईरान ने अपने नुकसान की पूरी जानकारी तो नहीं दी है। लेकिन कहा कि उसने अमेरिका को करारा जवाब दिया है।

प्र.मंत्री ने नीति आयोग की बैठक ली

मीटिंग में पहली बार सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया।

नई दिल्ली, 11 जून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में अल-नीनो की संभावित चुनौतियों को देखते हुए जल संरक्षण तथा प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने का आह्वान किया।

उन्होंने आकांक्षी जिलों के मानकों के आधार पर प्रागति के मूल्यांकन और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए स्पष्ट निगरानी व्यवस्था, 100-दिवसीय तथा पांच वर्षीय लक्ष्यों की आवश्यकता पर जोर दिया।

नीति आयोग की शीर्ष बैठक में पहली बार सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केन्द्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद बैठक की अध्यक्षता की। इस साल का विषय 'विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास' था। इसमें 28 राज्यों और 5 केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप-राज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए।

मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस

कांग्रेस का दावा नटराजन के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है

-जाल खंबाता-

राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो- नई दिल्ली, 11 जून। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन खारिज होने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नामांकन को रद्द किए जाने के खिलाफ शीर्ष न्यायालय में याचिका दायर की है।

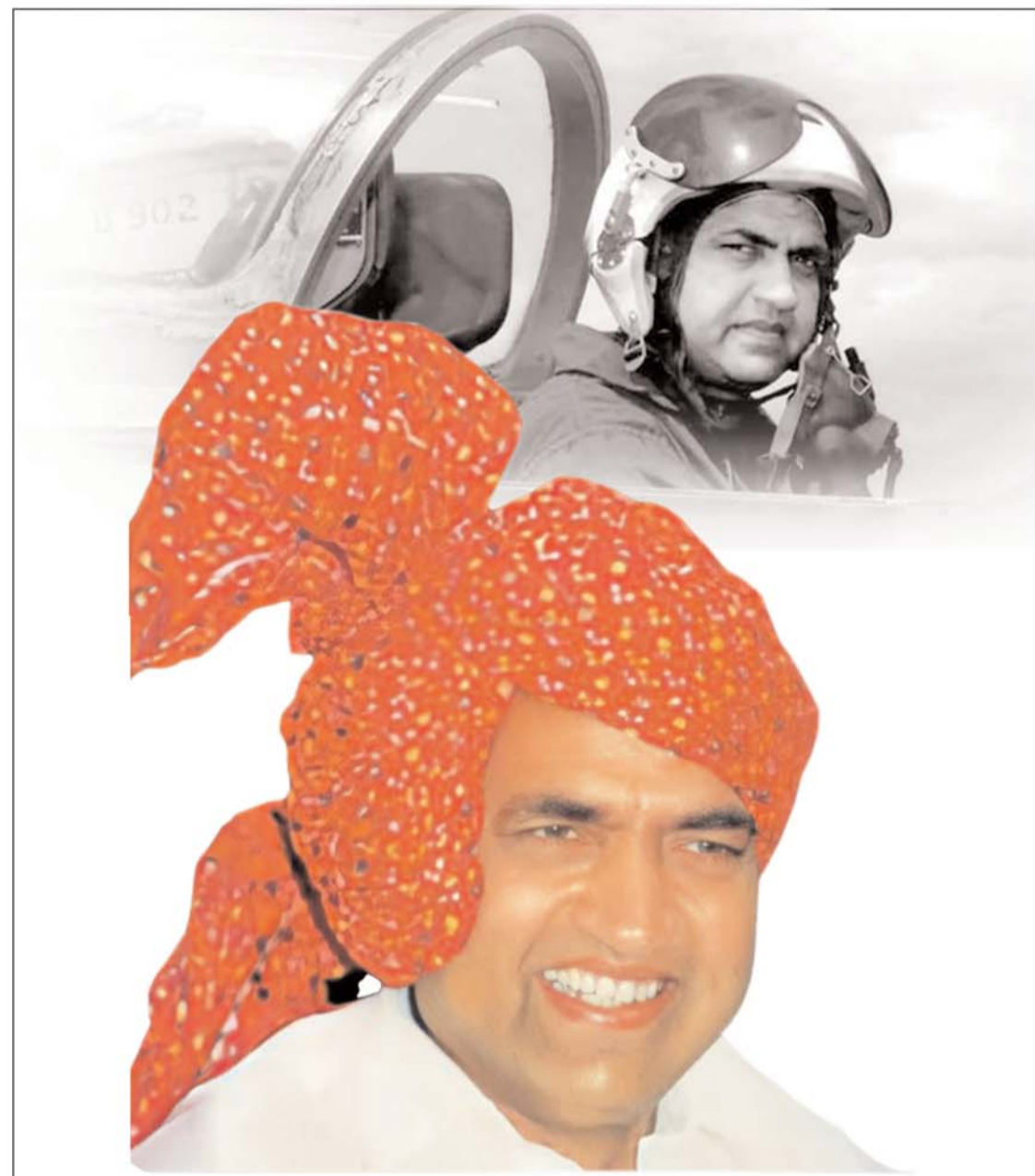
- कांग्रेस ने चुनाव आयोग में भी मध्य प्रदेश के रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ शिकायत की और तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की।
- मध्य प्रदेश से भाजपा के राज्यसभा प्रत्याशी महेश केवट के वकील के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया या चुनाव नतीजे घोषित करने पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया।

यह कानूनी कदम तब उठाया गया, जब रिटर्निंग ऑफिसर ने भाजपा द्वारा उठाई गई आपत्तियों के कारण, नटराजन के नामांकन पत्र खारिज कर दिए। सत्ताधारी पार्टी का दावा था कि कांग्रेस नेता ने अपने नामांकन पत्र के साथ दिए गए हलफनामे में तेलंगाना के एक

कानूनी मामले की जानकारी नहीं दी। लेकिन, नटराजन ने इन आरोपों को "राजनीतिक साजिश" करार देते हुए जोर देकर कहा कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं है और यह मुद्दा केवल एक निजी शिकायत से संबंधित था।

बुधवार को नटराजन ने आरोप लगाया कि रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) कम्प्रोमाइज्ड थे। वे वर्तमान सरकार के प्रवक्ताओं और फ्रंटल संगठन प्रमुखों की तरह काम कर रहे थे। उन्होंने कहा, "मैं पूरी जिम्मेदारी के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)



राजेश पायलट

10 फरवरी 1945 – 11 जून 2000

विचार बिन्दु

अज्ञानी के लिए खामोशी से बढ़कर कोई चीज नहीं और यदि उसमें यह समझाने की बुद्धि हो तो वह अज्ञानी नहीं रहेगा। -शेख सादी

राजस्थान की पंच गौरव योजना: स्थानीय संसाधनों से वैश्विक पहचान तक

राजस्थान की पंच गौरव योजना राज्य के विकास के फलक पर एक अभिनव और दूरदर्शी पहल है जो स्थानीय संसाधनों को वैश्विक पहचान दिलाने, रोजगार सृजन करने और राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने हेतु विकसित की गई है। यह योजना राज्य के प्रत्येक जिले की विशिष्टता को पहचान देकर उन्हें विकास के नए केंद्र के रूप में स्थापित करने पर केंद्रित है। 17 दिसंबर 2024 को आयोजित विभाग द्वारा शुरू किया गया यह कार्यक्रम राजस्थान सरकार की दूरदर्शी सोच का परिणाम है और बजट 2025-26 में इस योजना को गति प्रदान करने के लिए 550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह योजना राजस्थान को भारत के मानचित्र में अलग स्थान देगी और राज्य को स्वदेशी, स्थानीय और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

पंच गौरव योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के प्रत्येक जिले की पंच विशिष्ट पहचानों को चुनकर उन्हें विकास के मुख्य धारा में लाना है। प्रत्येक जिले से पांच तत्व या उत्पाद चुने गए हैं जिनमें एक उपज, एक प्रजाति, एक खेल, एक उत्पाद और एक पर्यटन स्थल शामिल हैं। कृषि विभाग एक उपज का चयन करता है, वन विभाग एक प्रजाति का, खेल विभाग एक खेल का, उद्योग विभाग एक उत्पाद का और पर्यटन विभाग एक पर्यटन स्थल का। यह पंचमुखी विकास मॉडल राज्य के समग्र विकास को बढ़ावा देता है और प्रत्येक जिले की विशिष्टता को राष्ट्रीय और वैश्विक मंच पर रखता है।

स्थानीय संसाधनों को वैश्विक पहचान दिलाने में पंच गौरव योजना की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजस्थान के प्रत्येक जिले की अपनी विशिष्ट उपज, वनस्पति, खेल, हस्तशिल्प और पर्यटन स्थल हैं जो सदियों से उस जिले की पहचान बनकर रहे हैं। कोटा जिले का धनिया, खैर वृक्ष, कुश्ती, कोटा डोरिया और चंबल रिवर फ्रंट जैसे पंचगौरव इस जिले की विशिष्ट पहचान हैं। इन संसाधनों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए योजना के तहत विस्तृत कार्ययोजना बनाई गई है जिसमें मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ट्रेड शो और इंटरनेशनल एक्सपोजर शामिल हैं।

योजना के तहत प्रत्येक जिले के पंचगौरव को अंतरराष्ट्रीय मंच पर रखने के लिए विशेष अभियान शुरू किए गए हैं। इनमें जिले की विशिष्ट उपजों को विदेशी देशों में मार्केट किया जाएगा, हस्तशिल्प उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय ट्रेड शो में प्रदर्शित किया जाएगा और पर्यटन स्थलों को विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाया जाएगा। इससे राजस्थान के स्थानीय संसाधनों को वैश्विक पहचान मिलेगी और राज्य की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी।

रोजगार सृजन में पंच गौरव योजना का महत्व अत्यंत विशिष्ट है। प्रत्येक जिले के पंचगौरव के विकास से कृषि, वन, खेल, उद्योग और पर्यटन क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है। कृषि विभाग द्वारा चुने गए उपज के विकास के लिए नई तकनीक और मार्केटिंग के अवसर मिलेंगे जिससे उनके उत्पादन और बिक्री में वृद्धि होगी। वन विभाग द्वारा चुने गए प्रजाति के संरक्षण और विकास से वन क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिलेंगे। खेल विभाग द्वारा चुने गए खेल के विकास से युवाओं को खेल क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिलेंगे। उद्योग विभाग द्वारा चुने गए उत्पाद के विकास से स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर मिलेंगे। पर्यटन विभाग द्वारा चुने गए पर्यटन स्थल के विकास से पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के माध्यम मिलेंगे।

पंच गौरव योजना का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले के पंचगौरव का विकास होगा और उन्हें राष्ट्रीय और वैश्विक मंच पर रखा जाएगा। इससे राजस्थान की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे और राज्य आत्मनिर्भर बन जाएगा।

हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों के विकास में रोजगार के अवसर मिलेंगे और उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे।

“स्वदेशी, स्थानीय और आत्मनिर्भर” की भावना को टोस आधार प्रदान करने में पंच गौरव योजना की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह योजना स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके स्थानीय उत्पादों को विकसित करने और उन्हें राष्ट्रीय और वैश्विक मंच पर रखने पर केंद्रित है। इससे राजस्थान की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और राज्य आत्मनिर्भर बन जाएगा। योजना के तहत स्थानीय उत्पादों को ब्रांडिंग और मार्केटिंग के अवसर दिए जाएंगे जिससे उनकी बिक्री में वृद्धि होगी और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।

राजस्थान को भारत के मानचित्र में अलग स्थान देने में पंच गौरव योजना की भूमिका अत्यंत विशिष्ट है। यह योजना राज्य की विशिष्टता को राष्ट्रीय और वैश्विक मंच पर रखती है और राज्य को विकास के नए केंद्र के रूप में स्थापित करती है। प्रत्येक जिले के पंचगौरव को अंतरराष्ट्रीय मंच पर रखने के लिए विशेष अभियान शुरू किए गए हैं जिससे राजस्थान को भारत के मानचित्र में अलग स्थान मिलेगा।

योजना के तहत राज्य की विशिष्ट उपजों, हस्तशिल्प उत्पादों और पर्यटन स्थलों को विदेशी देशों में मार्केट किया जाएगा जिससे राजस्थान को वैश्विक मंच पर पहचान मिलेगी। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी और राजस्थान को भारत के मानचित्र में अलग स्थान मिलेगा।

पंच गौरव योजना का कार्यान्वयन जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय समितियों द्वारा किया जाएगा। जिला स्तरीय समितियाँ प्रत्येक जिले के पंचगौरव का चयन और विकास कार्यक्रमों को बनाएंगी। राज्य स्तरीय समिति जिला स्तरीय प्रस्तावों और कार्ययोजनाओं का परीक्षण कर उन्हें अंतिम मंजूरी देगी। 8 सितंबर 2025 को राज्य स्तरीय समिति की बैठक हुई थी जिसमें जिला स्तरीय प्रस्तावों और कार्ययोजनाओं का परीक्षण कर उन्हें अंतिम मंजूरी दी गई थी।

योजना के कार्यान्वयन में विभिन्न विभागों का सहयोग आवश्यक है। कृषि विभाग एक उपज के विकास में, वन विभाग एक प्रजाति के संरक्षण और विकास में, खेल विभाग एक खेल के विकास में, उद्योग विभाग एक उत्पाद के विकास में और पर्यटन विभाग एक पर्यटन स्थल के विकास में सहयोग देंगे। यह पंचमुखी विकास मॉडल राज्य के समग्र विकास को बढ़ावा देता है।

पंच गौरव योजना का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले के पंचगौरव का विकास होगा और उन्हें राष्ट्रीय और वैश्विक मंच पर रखा जाएगा। इससे राजस्थान की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे और राज्य आत्मनिर्भर बन जाएगा। योजना के तहत युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए स्वर्ण अवसर प्रदान किए गए हैं जिससे राज्य के समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा।

योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार ने विस्तृत कार्ययोजना बनाई है जिसमें मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ट्रेड शो और इंटरनेशनल एक्सपोजर शामिल हैं। इससे राजस्थान के स्थानीय संसाधनों को वैश्विक पहचान मिलेगी और राज्य की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी। पंच गौरव योजना राजस्थान के विकास के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ती है। यह योजना स्थानीय संसाधनों को वैश्विक पहचान दिलाने, रोजगार सृजन करने और राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

योजना के सफल कार्यान्वयन से राजस्थान की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, रोजगार के अवसर खुलेंगे, और राज्य आत्मनिर्भर बन जाएगा। यह योजना राजस्थान के विकास के नए मॉडल को प्रस्तुत करती है जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके स्थानीय उत्पादों को विकसित करने और उन्हें राष्ट्रीय और वैश्विक मंच पर रखने पर केंद्रित है।

पंच गौरव योजना राजस्थान के लिए एक नया अवसर है जो राज्य को विकास के नए केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। यह योजना स्थानीय संसाधनों को वैश्विक पहचान दिलाने, रोजगार सृजन करने और राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह योजना राजस्थान को भारत के मानचित्र में अलग स्थान देगी और राज्य को स्वदेशी, स्थानीय और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

-अतिथि संपादक,
अविनाश जोशी,
वरिष्ठ पत्रकार एवं आर्थिक सलाहकार

नए और सशक्त भारत का उदय

नरेन्द्र मोदी सरकार के ऐतिहासिक 12 वर्ष



डॉ. सतीश पुनिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले बारह वर्षों में भारत ने एक विकसित, आत्मविश्वास से लबरेज और दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले मजबूत राष्ट्र के रूप में पहचान कायम की है। भारत के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उथान की गथाएं दुनिया की जुबान पर हैं। अब वह दौर नहीं रहा, जब आतंक फैलाने वाले मुल्क को देश में आतंकी घटनाओं में उसकी स्पष्ट संलिप्तता के बावजूद भी उसे दंडित करने के स्थान पर उसको डोजियर पर डोजियर सौंपा जाए, अब सीधी और स्पष्ट कार्रवाई होती है। यह सब संभव हुआ है एक कुशल, विजयी और राष्ट्र प्रथम की भावना वाले नेतृत्व के कारण।

मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार यह जानती थी कि दुनिया के सामने खड़ा होना है तो हमें पहले आर्थिक ताकत बनाना होगा। भारतीय नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक तौर पर सशक्त करना होगा। पिछले बारह वर्षों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था और देश के नागरिकों को सशक्त करने का काम किया है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि

वर्तमान में जब पूरी दुनिया मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की आग से झुलस रही है, उस दौर में भी भारतीय अर्थव्यवस्था 7.7 की उत्साहजनक वार्षिक वृद्धि दर से आगे बढ़ रही है। 40 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे छोटे उद्यमियों के हाथों में सौंपी गई है। इसमें लगभग 68 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं और समाज के पिछड़े तबके से हैं। महंगी दवाओं और ईलाज को आसान बनाते हुए मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के माध्यम से स्वास्थ्य सुरक्षा को बिलकुल कल्याणकारी बना दिया गया है। देशभर में खुले हजारों जन औषधि केंद्रों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं बाजार मूल्य से पचास से नब्बे प्रतिशत तक कम कीमत पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में कनेक्टिविटी पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मोदी सरकार ने पिछले बारह वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की गति और कवरेज में क्रांतिकारी बदलाव किया है। इन वर्षों में ग्रामीण कनेक्टिविटी को अभूतपूर्व गति देते हुए सात लाख किलोमीटर से अधिक लंबी ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। इसका असर यह हुआ है कि इन बारहमासी सड़कों ने न केवल किसानों को फसलों को मंडियों तक आसानी से पहुंचाया है, बल्कि ग्रामीण अंचलों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को भी सुलभ किया है।

जल जीवन मिशन के माध्यम से महिलाओं सशक्तिकरण का ऐतिहासिक कार्य किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जल जीवन मिशन की घोषणा की और इसे एक जन-आंदोलन बना दिया। ग्रामीण इलाकों में पाइप से पानी

का दायरा आज बढ़कर पंद्रह करोड़ से अधिक घरों तक पहुंच चुका है। इस योजना ने ग्रामीण भारत, विशेषकर महिलाओं को पानी से होने वाली गंधीर बीमारियों से मुक्ति दी है।

महिला सशक्तिकरण के साथ यह योजना इज ऑफ लिविंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। कोविड महामारी के दौरान जब पूरी दुनिया थम गई थी। लोग घरों में कैद हो गए थे। लोगों के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई थी, उस दौर में मोदी सरकार ने सुनिश्चित किया कि देश का कोई भी गरीब परिवार भूखा न सोए। सौभाग्य से उस वक्त राजस्थान प्रदेश का भाजपा अध्यक्ष होने के नाते हमने प्रधानमंत्रीजी के निर्देशन में प्रदेश में यह सुनिश्चित किया कि पार्टी की तरफ से लोगों तक अधिक से अधिक सहायता पहुंचावै जाए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन की यह व्यवस्था आज भी अनवरत जारी है। देश के 81 करोड़ से अधिक नागरिकों को हर महीने मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जा रहा है।

हर सर पर छत के मिशन के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से अब तक चार करोड़ से अधिक पक्के घरों का निर्माण किया गया और उन्हें गरीब और बेघर परिवारों को सौंपा जा चुका है। हाल ही में प्रधानमंत्री ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजना के अगले चरण को भी मंजूरी दे दी गई है। इसी तरह डायरेक्ट बेंचिफिट ट्रांसफर के माध्यम से विभिन्न केंद्रीय योजनाओं का 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक का फंड सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया यह पादश्री और प्रगति चक्र मुक्त शासन का सबसे बड़ा कल्याणकारी नीतियों ने भारत से गरीबी उन्मूलन के कार्य को एक अभूतपूर्व गति

दी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, विजली, आवास और स्वच्छता के मोर्चे पर चौरफा सुधार के कारण पिछले एक दशक में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी के जाल से बाहर आए हैं।

पाठकों को याद होगा कि 2014 से पहले स्वच्छता भारत की प्राथमिकताओं में कहीं पीछे छूट गई थी। लेकिन जब लाल किले से जब प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन का आह्वान किया। देशभर में रिकॉर्ड समय के भीतर 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया, जिससे ग्रामीण स्वच्छता का दायरा 2014 के 39 प्रतिशत से बढ़कर अब शत-प्रतिशत हो चुका है। यह केवल एक स्वच्छता अभियान नहीं था, बल्कि यह देश की करोड़ों महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और स्वास्थ्य से जुड़ा एक ऐतिहासिक सामाजिक सुधार आंदोलन था। देश के श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिए मोदी सरकार ने ई-श्रम पोर्टल और विभिन्न पेंशन तथा बीमा योजनाओं के माध्यम से उनको संरक्षण देने की पहल की। आज देश के 31 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में शामिल हो चुके हैं। मोदी सरकार ने इन 12 वर्षों में देश की राजनीति के व्याकरण को बदल दिया है। 2014 से पहले की राजनीति महज जातिगत समीकरणों, तुष्टिकरण और वोटबैंक के इर्द-गिर्द घूमती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित की। आज का भारत एक आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है, जो अपनी कमियों को पीछे छोड़ते हुए वैश्विक पटल पर एक महाशक्ति बनने की ओर कदम बढ़ा चुका है।

-डॉ. सतीश पुनिया,
(हरियाणा भाजपा प्रदेश प्रभारी एवं राज्याध्यक्ष सांसद)

कैसे मिलें ईमानदार, संवेदनशील और जनहित को समर्पित प्रशासक?



राजेन्द्र भाणावत

आप कोई भी समाचार पत्र उठा लें, प्रशासन की संवेदनहीनता के समाचार निरंतरता के साथ प्रकाशित हो रहे हैं। प्रशासक चाहे वे किसी भी विभाग के क्यों न हों, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, पुलिस, खान, कर, परिवहन आदि। इन सब विभागों के मुखिया अधिकारताय आईएसएस, आईपीएस, आईएएस, आरपीएस या अन्य अखिल भारतीय और राज्य सेवा के अधिकारी हैं। यदि सरकार के कामकाज में संवेदनशीलता लानी है, तो ईमानदार प्रशासकों और लोक सेवकों की संख्या को बढ़ाना होगा। इस हेतु सरकार को महत्वपूर्ण आवश्यक कदम उठाने होंगे। इनके बिना संवेदनशील और ईमानदार प्रशासन की कल्पना, कोरी कल्पना ही बनी रहेगी।

पहले लोक सेवकों कि चयन प्रक्रिया को ही लें। इसमें आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है।संलग्न सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग की वर्तमान व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के विभिन्न विषयों से संबंधित जानकारी का ही आकलन करती है। यह सोच ही सही नहीं है कि भौतिक, इतिहास, समाजशास्त्र या कानून जैसे विषयों में अच्छे अंक लाने वाला अच्छा अधिकारी सिद्ध होगा प्रॉलिम्स और मंस परीक्षा पर करने के बाद साक्षात्कार के दौरान भी 20 से 30 मिनट में किसी भी व्यक्ति के बारे में यह आकलन करना संभव नहीं हो सकता कि वह आने वाले 30-35 वर्षों तक किस प्रकार की मानसिकता के साथ काम करेगा? गत कुछ वर्षों से ऐसे संवेदनशील और ईमानदार अधिकारियों की संख्या निरंतर घटती जा रही है। कुछ दशक पूर्व तक

संभवतया संवेदनशील अधिकारी मिल पाए थे, किंतु अब तो यह दुर्लभ सा हो गया है। विषय विशेषज्ञ और तकनीकी रूप से परांगत अधिकारी की नौयत यदि अच्छी नहीं है तो वह कहीं अधिक नुकसान समाज को पहुंचा सकता है। आज हम ऐसा ही कुछ देख रहे हैं। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिसका किसी सरकारी विभाग से वास्ता पड़ा हो, तो उसकी धारणा भी लगभग ऐसी ही होगी।

चयन की सर्वाधिक उपयुक्त प्रणाली संभवतया सेना में अधिकारियों की भर्ती के लिए है। लगभग चार या पांच दिन तक अभ्यर्थियों को मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों की सतत निगरानी में रखा जाता है और उन्हें विभिन्न प्रकार की स्थितियों से गुजरना पड़ता है। बनावटी तौर पर, कोई व्यक्ति 15-20 मिनट तक तो स्वयं को संवेदनशील सिद्ध कर भी दे, किंतु चार-पांच दिन तक लगातार ऐसा कर पाना उसके लिए संभव नहीं होता और उसके व्यक्तित्व के वास्तविक गुण स्पष्टतया प्रकट हो जाते हैं। संघ सेवा आयोग और राज्य सेवा आयोगों को भी इस प्रकार की प्रणाली के आधार पर अपनी चयन प्रक्रिया को बिलकुल बदलना होगा। प्रारंभ में इसे साक्षात्कार के स्तर पर लागू किया जा सकता है, बाद में इसे प्रॉलिम्स और लिखित मुख्य परीक्षा के स्तर पर भी लागू किया जा सकता है। प्रश्न पत्र भी किसी विषय विशेष की जानकारी का मूल्यांकन करने के बजाय विभिन्न परिस्थितियों में उसका दृष्टिकोण क्या रहता है, उसका आकलन करने वाला हो सकता है। परिणामस्वरूप, कहीं अधिक उपयुक्त लोक सेवकों के चयन की संभावना रहेगी। किसी भी व्यक्ति को गणित, भौतिक शास्त्र, इतिहास या नागरिक शास्त्र में कितने अंक प्राप्त हुए, उससे यह निर्धारित नहीं होता कि कोई व्यक्ति जनहित के प्रति समर्पित प्रशासक सिद्ध होगा या नहीं। यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या ऐसे अधिकारियों को मंत्री और अन्य जनप्रतिनिधि पदें देंगे? यदि देश को संविधान के प्रति प्रतिबद्ध, निष्ठावान, ईमानदार अधिकारियों की वास्तव में आवश्यकता है तो ऐसे ही अधिकारियों का चयन होना चाहिए। अधिकारियों के लिए निर्धारित गुण केवल जनप्रतिनिधियों की सुविधा

के अनुसार ही तय नहीं किए जा सकते। देश के 150 करोड़ लोगों के हित को सर्वोपरि रखने वाले और उनके प्रति संवेदनशीलता रखने वाले अधिकारी का कोई विकल्प नहीं हो सकता।

सही चयन के पश्चात प्रशिक्षण व्यवस्था में भी बहुत बदलाव करना होगा। मसूरी, हैदराबाद और जयपुर स्थित प्रशिक्षण संस्थाओं में वर्तमान की तरह केवल विषयों का सैद्धांतिक ज्ञान या जानकारी देने की अधिक आवश्यकता नहीं है। आजकल तकनीक के युग में किसी भी विषय की पूरी जानकारी, अधिकारी, अपने स्तर पर इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। उसे विषय वस्तु की जानकारी देना अथवा कानून के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी देना, समय को व्यर्थ करना हो सकता है। इसके बजाय उसे विद्यार्थी प्रतिष्ठित, अनुभवी, संवेदनशील अधिकारियों के साथ खुले संवाद का अधिकतम अवसर देना चाहिए, जिससे वह ऐसे प्रशासकों को जीवन शैली और कार्य प्रणाली पर चर्चा करके उसे आमंत्रित करने का प्रयास कर सके।

ऐसे बात करनी है कि आज अच्छे प्रशासकों का नितांत अभाव हो। ऐसे प्रशासक और पुलिस अधिकारी एवं अन्य सेवाओं के अधिकारी अभी भी सेवा में उपलब्ध हैं या सेवा निवृत्त हैं, जो नवनि्युक्त अधिकारियों के लिए रोल मॉडल का काम कर सकते हैं। बस करना यह है कि ऐसे अधिकारियों का चयन किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह और भेदभाव के बिना सही लोगों के द्वारा किया जाए। प्रशिक्षण के लिए प्रभावी तरीका, केस स्टडीज पर चर्चा करना है। केस स्टडीज को वास्तविक हीं और अच्छी तरह लिखी हुई हो तो वे प्रशासकों में वांछित दक्षता विकसित करने के लिए काम आ सकती हैं। ऐसी केस स्टडीज को एकत्रित किया जाना चाहिए और उन पर किसी निष्णात प्रशिक्षक के माध्यम से प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ चर्चा की जानी चाहिए। जब तक इस प्रकार का प्रशिक्षण केवल व्यावहारिक आधारित रहेगा, तब तक उसका अधिक प्रभाव नहीं होगा। दुर्भाग्य से अधिकांश प्रशिक्षण संस्थाओं में आजकल यही हो रहा है।

प्रशिक्षण में उन्हें आधुनिकतम तकनीक में परिचित किया जा सकता है, किंतु उन्हें यह भी समझाया जाय कि

तकनीक केवल साधन है, साध्य नहीं। सेना के प्रशिक्षण संस्थानों में श्रेष्ठतम व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। जबकि राज्यों के प्रशिक्षण संस्थानों में अधिकांशतया अधिकारियों को, अपवादों को छोड़कर, बतौर सजा लगाया जाता है। वास्तव में यह सजा इन अधिकारियों के बजाय उन्हें अधिक मिथती है जो इस आधारों में वहां प्रशिक्षण के लिए आते हैं। राज्य के प्रशिक्षण संस्थानों में भी श्रेष्ठतम अधिकारियों को चयन के आधार पर, नियुक्त किया जाना आवश्यक है, ताकि वे प्रशिक्षणार्थियों में ऊर्जा और उत्साह का संचार कर सकें।

यह बात अधिकारियों के दिलों दिग्गम में अच्छी तरह बिठाई जा सकती है कि उनकी प्रतिबद्धता केवल और केवल देश के लोगों के प्रति, संविधान के माध्यम से है। जिस स्टील फ्रेम की बात सरदार वल्लभभाई पटेल ने कही थी, उसकी आवश्यकता जितनी आज है, उतनी शायद पहले कभी नहीं थी। आज के अधिकारियों की रीढ़ की हड्डी बहुत लचीली हो गई है। लाता है स्टील में जंग लगा गया है। देश के चाहे आईएसएस अधिकारी हों या आईपीएस अधिकारी, सब जिस प्रकार सत्ता के बदलते ही अपना रंग बदल लेते हैं, उसे देखकर रिगिस्ट भी शरमा जाए।यह चिंता का विषय है। सत्ताधारी दल, प्रजातंत्र में बदलते रहेंगे, किंतु स्थाई सेवा में नियुक्त अधिकारियों, विशेष कर उच्च सेवा के अधिकारियों को, अपने कर्तव्य करने के तरीके को इस प्रकार संवेदनशील और निष्पक्ष रखना होगा जैसी उनसे सरदार पटेल ने अपेक्षा की थी। तब ही, वे अपनी सेवा के प्रति एवं जनता के प्रति न्याय कर पाएंगे। एक और बड़ा कारण जो अधिकारियों को ईमानदार और संवेदनशीलता के मार्ग से हट कर जाता है, वह है जवाब देही का नितांत अभाव।

श्रेष्ठ अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई एक-दो दिन की हेडलाइंस बनती है लेकिन कुछ समय बाद वही अधिकारी अपनी सेवा में वेदोषित की सीढ़ियां चढ़ते हुए सर्वोच्च पदों तक चढ़ते हुए देखे जाएंगे। जब किसी अधिकारी को श्रेष्ठ तरीके अपनाते पर किसी प्रकार की तत्काल कड़ी सजा का इंत नही होगा, तो विरले अधिकारी ही ईमानदार की राह पर चलना पसंद करेंगे। आज वही ज़ाकदी सिविल सेवा के साथ में है। वे देखते हैं कि बेईमान अधिकारी, केवल

चाटुकारिता के बल पर आगे बढ़ जाते हैं, जबकि जनता के प्रति समर्पित ईमानदार अधिकारी कई बार सत्ताधारी दल के जनप्रतिनिधियों के कोप के भाजन बन जाते हैं। संवेदनहीन और बेईमान अधिकारियों को सजा देने के लिए यदि कानूनी प्रक्रिया में संशोधन की भी आवश्यकता हो तो, उसे करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। एक बार जब सही प्रकार के अधिकारी मिल जाए, तो फिर बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगी और जनता को उनकी अपेक्षा के अनुसार शासन व्यवस्था उपलब्ध हो पाएगी।

डेढ़ सौ करोड़ की जनसंख्या वाले देश में प्रतिवाचों की कोई कमी नहीं है। यदि उनकी प्रगति में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो यह स्वार्थ अथवा दबाव के कारण होती है। हमने हाल ही में अभी, सीबीएसई और नीट की परीक्षा में देखा है कि किस प्रकार अपने व्यक्तिगत लोभ के लिए लोग लाखों युवाओं का भविष्य दौब पर लगा देते हैं।

अपेक्षा कुछ सुझाव लेखक ने अपने दीर्घ प्रशासनिक अनुभव और अनुभव सेवामित के बाद समाज के विभिन्न वर्गों से चर्चाओं के आधार पर दिए हैं। आशा है, लोक सेवा आयोग और सरकारें इस ओर गंभीरता से ध्यान देंगे ताकि देशवासियों को संवेदनशील और ईमानदार, जनहितकारी शासन मिल सके जिसके वे हकदार हैं।

-राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.एस. अधिकारी)

राशिफल

शुक्रवार 12 जून, 2026

द्वितीय ज्येष्ठ मास (अधिक), कृष्ण पक्ष, द्वादशी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत् 2083, अश्विनी नक्षत्र प्रातः 6:29 तक, अतिगंड योग रात्रि 9:26 तक, कोलव करण प्रातः 9:07 तक, चन्द्रमा आज मेष राशि में संचार करेगा।
ग्रह स्थिति: सूर्य-चूच, चन्द्रमा-मेष, मंगल-मेष, बुध-मिथुन, गुरू-कर्क, शुक्र-कर्क शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

पंडित अनिल शर्मा

आज सर्वाथि सिद्धि योग प्रातः 6:29 तक है। राजयोग प्रातः 6:29 से योग रात्रि 7:37 तक है। आज प्रदोष व्रत है।

श्रेष्ठ चौघडिया: चर सूर्योदय से 7:19 तक, लाभ अमृत 7:19 से 10:44 तक, शुभ 12:27 से 2:09 तक, चर 5:34 से सूर्यास्त तक।
राहुकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 5:36, सूर्यास्त 7:17।

मेघ

मानसिक तनाव दूर होगा। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यक्तिगत प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। घर-परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

तुला

व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। नौकरपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा।

वृश्चिक

विवादित मामलों का निपटारा हो सकता है। अटक हुए कार्य बने लगे। अस्त-व्यस्त दिवसों में सुधार होगा। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

धनु

परिजनों के व्यवहार के कारण मन खिन्न हो सकता है। आवश्यक और महत्वपूर्ण मामलों में दुविधा बनी रहेगी। व्यक्तिगत परेशानियां यथावत बनी रहेगी।

मकर

घर-परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। अतिथियों का आगमन बना रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ

व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक मामलों से संबंधित विवादों का निपटारा हो सकता है।

मीन

व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

कन्या

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है। यात्रा में दुर्घटना का भय है।

नकली खाद-बीज पर शिकंजा : कृषि मंत्री ने कानोता के हीरावाला की फैक्ट्री पर मारा छापा

रीको क्षेत्र में कार्रवाई से हड़कंप मचा, जब्त नमूने जांच के लिए भेजे

-कार्यालय संवाददाता- जयपुर। प्रदेश में नकली खाद और बीज के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने गुरुवार को जयपुर के कानोता क्षेत्र स्थित हीरावाला रीको औद्योगिक क्षेत्र में संचालित 'जयपुर बायो फर्टिलाइजर्स' इकाई पर औचक निरीक्षण कर बड़ी कार्रवाई की। मंत्री के आचानक पहुंचने



कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने गुरुवार को कानोता क्षेत्र स्थित हीरावाला रीको औद्योगिक क्षेत्र में संचालित 'जयपुर बायो फर्टिलाइजर्स' इकाई पर औचक निरीक्षण कर कार्रवाई की।



कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने गुरुवार को कानोता क्षेत्र स्थित हीरावाला रीको औद्योगिक क्षेत्र में संचालित 'जयपुर बायो फर्टिलाइजर्स' इकाई पर औचक निरीक्षण कर कार्रवाई की।

■ मंत्री किरोड़ीलाल ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी

से फैक्ट्री संचालकों और आपसपास के औद्योगिक क्षेत्र में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान जैविक उर्वरक निर्माण और भंडारण से जुड़ी कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं, जिसके बाद कृषि विभाग ने नमूने जब्त कर जांच शुरू कर दी है।

निरीक्षण के दौरान पता चला कि जैविक उर्वरक का निर्माण निर्धारित तकनीकी मानकों के विपरीत किया जा रहा था। विशेषज्ञों के अनुसार जैविक खाद में मौजूद लाभकारी सूक्ष्मजीवों को सुरक्षित रखने के लिए निर्माण प्रक्रिया के दौरान तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, लेकिन फैक्ट्री में खाद 45 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तैयार की जा रही थी।

अधिकारियों के अनुसार इतने अधिक तापमान पर लाभकारी सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं और उत्पाद की गुणवत्ता प्रभावित होती है। जांच में लेबलिंग से जुड़ा बड़ा फर्जीबादा भी सामने आया। दानेदार जैविक उर्वरक को सामान्य शेलफ लाइफ छह माह होती है, जबकि उत्पाद के पैकेटों पर 24 माह तक उपयोग योग्य होने का उल्लेख किया गया था। इसके अलावा कच्चे माल के भंडारण और रख-रखाव में भी गंभीर लापरवाही पाई गई। गोदाम में रखे कच्चे माल पर पहचान संबंधी आवश्यक लेबल नहीं लगे थे, जो

उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 की धारा 19 का उल्लंघन माना गया है। मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने स्वयं फैक्ट्री परिसर का निरीक्षण किया और कई सोलबंद कट्टों को खुलवाकर खाद की गुणवत्ता की जांच की। विभागीय अधिकारियों ने विभिन्न उत्पादों के नमूने लेकर परीक्षण के लिए सरकारी प्रयोगशाला भेज दिए हैं। साथ ही फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में मौजूद खाद और बीज के स्टॉक की भी जांच की जा रही है।

कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के हितों के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नकली खाद और घटिया बीज बेचने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा तथा दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अन्नदाताओं की मेहनत की कमाई से धोखाधड़ी करने वालों को किसी भी सूत्र में नहीं छोड़ा जाएगा।

कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यदि नमूने अमानक या नकली पाए गए तो संबंधित फैक्ट्री संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ-साथ लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी। उल्लेखनीय है कि डॉ. किरोड़ी लाल मीणा इससे पहले भी सीकर के रीको क्षेत्र स्थित श्री बालाजी एग्री इंस्टीट्यूट, जोधपुर की विभिन्न खाद-बीज निर्माण इकाइयों तथा बोरानाडा स्थित बालाजी मूंगफली फैक्ट्री सहित कई प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण और छापामार कार्रवाई कर चुके हैं। कृषि विभाग का कहना है कि प्रदेशभर में गुणवत्तापूर्ण खाद और बीज उपलब्ध कराने तथा नकली कृषि उत्पादों के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से औद्योगिक विकास फास्टट्रैक पर

सीकर, रींगस, फुलेरा, ब्यावर और सिरौही से गुजर रहे कॉरिडोर से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिल रही नई गति

-कार्यालय संवाददाता- जयपुर। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डब्ल्यूडीएफसी) के माध्यम से देश-प्रदेश में औद्योगिक विकास तेजी से फास्टट्रैक पर दौड़ रहा है।

कॉरिडोर में विशेषकर रेल-पर-ट्रक की सेवा से माल का आवागमन अधिक तेज और सुगम बना है। जवाहर लाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल (जेएनपीटी) से दारदी तक फैले इस वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लम्बाई 1506 किमी. एवं लागत 1.24 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। कॉरिडोर का लगभग 39 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरता है। यह कॉरिडोर राजस्थान को भारत के उत्तरी एवं पश्चिमी बाजारों तक बेहतर संपर्क प्रदान करता है। कॉरिडोर के अंतर्गत जेएनपीटी से न्यू सफाले (वेतरणा) सेक्शन पर हाल ही में सफलतापूर्वक ट्रायल रन हो चुका है। इस कॉरिडोर का काम पूर्ण हो चुका है। कई सेक्शन में माल परिवहन पहले से ही प्रारंभ है।

यह कॉरिडोर राजस्थान के सीकर, रींगस, फुलेरा, ब्यावर, सिरौही से होकर गुजर रहा है। जिससे इन जिलों के साथ-साथ अन्य स्थानों के उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। हाल ही में अजमेर के सराधना में नए गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है। इस टर्मिनल में आधुनिक कार्गो हैंडलिंग अवसंरचना, वेयरहाउसिंग

■ राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच से लोकल बनेगा ग्लोबल

■ जेएनपीटी से दारदी तक 1506 किमी. तक फैला कॉरिडोर, 1.24 लाख करोड़ रुपये की लागत से तैयार

■ कॉरिडोर का लगभग 39 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान में, उत्तरी-पश्चिमी बाजारों तक बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध

सुविधाएं तथा निर्बाध मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई है, जिससे उद्योगों एवं व्यापारियों के लिए माल परिवहन अधिक तेज, सुरक्षित एवं किफायती होगा। यह टर्मिनल प्रति माह लगभग 40 रोक (लागभग 1.5 मिलियन टन प्रति वर्ष) कार्गो हैंडल करने में सक्षम होगा, जिसमें मार्बल, ग्रेनाइट, खनिज तथा अन्य वस्तुएं शामिल हैं। यानि किशनगढ़ के मार्बल को कॉरिडोर के उच्च गति माल परिवहन नेटवर्क के माध्यम से जेएनपीटी, पीपावाव एवं मुंद्रा बंदरगाहों तक पहुंचाया

जाएगा। इससे लोकल फॉर ग्लोबल का संकल्प साकार होगा।

यह कॉरिडोर लॉजिस्टिक्स अवसंरचना को सुदृढ़ करने के साथ ही माल परिवहन को तेजी से बढ़ाने की दीर्घकालिक पहल है। सामान्य कॉरिडोर की तुलना में 66 प्रतिशत वृद्धि के साथ इस कॉरिडोर की ऊंचाई 7.1 मीटर और 14 प्रतिशत वृद्धि के साथ चौड़ाई 3660 एमएम रखी गई है। ट्रेन की लम्बाई 1500 मीटर है, जबकि सामान्य कॉरिडोर में 700 मीटर ही होती है। वहीं, डबल क्रन्टेनर स्टेक और 2.4 प्रतिशत ट्रेन लोड की क्षमता भी इस कॉरिडोर में उपलब्ध है। इस कॉरिडोर में ट्रेन की रफ्तार भी औसतन 25 किमी. से बढ़ाकर 65 किमी. प्रति घण्टे की गई है। उल्लेखनीय है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसमें पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अंतर्गत दारदी से जेएनपीटी एवं पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तहत लुधियाना से डंकुनी तक जोड़ा गया है। यह परियोजना देश का लगभग 70 प्रतिशत माल परिवहन करने के उद्देश्य से बनाई गई है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के दोनों तरफ 150 किलोमीटर का प्रभाव क्षेत्र दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत खुशखेडा-भिवानी-नीमराना निवेश क्षेत्र और जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं।

रेल मंत्री के कार्यक्रम में तीन बार गुल हुई बिजली

13 मिनट अंधेरे में बोले अश्विनी वैष्णव

-कार्यालय संवाददाता- जयपुर। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में गुरुवार को आयोजित केंद्रीय रेल, इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के मीडिया संवाद कार्यक्रम के दौरान बिजली व्यवस्था चर्चा का विषय बन गई। कार्यक्रम के बीच तीन बार बिजली गुल हुई, जिससे मीडिया हॉल में अंधेरा छा गया। एक बार बिजली करीब 13 मिनट तक नहीं आई, जिसके चलते रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अंधेरे में ही पत्रकारों को संबोधित किया। उस समय राज्य के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी मंच पर मौजूद थे, लेकिन कुछ देर इंतजार के बाद वे हॉल से बाहर चले गए और बिजली बहाल होने पर वापस लौटे।

बिजली कटौती के बीच आयोजित मीडिया संवाद में अश्विनी वैष्णव ने मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों और राजस्थान में हुए विकास कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के समय राजस्थान को रेलवे के लिए केवल

■ भाजपा प्रदेश मुख्यालय में मीडिया संवाद के दौरान बाधित हुई बिजली आपूर्ति

■ ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर बीच में हॉल से बाहर निकले

682 करोड़ रुपये का बजट मिलता था, जबकि वर्तमान में यह बढ़कर 10,828 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में लगभग 76 हजार करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न रेल परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। कार्यक्रम से पूर्व अश्विनी वैष्णव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और संगठन महामंत्री अजय कुमार ने मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनों का उद्घाटन किया। रेल मंत्री ने बताया कि राजस्थान के 85 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा

रहा है, जिनमें जयपुर, गांधी नगर, जोधपुर, जैलमर, बीकानेर, कोटा, अजमेर और अलवर सहित कई प्रमुख स्टेशन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बाद राजस्थान को 46 नई रेलगाड़ियां मिली हैं और अजमेर-जयपुर-दरभंगा रेल सेवा को नियमित रूप से संचालित करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही राज्य में कई रेल लाइन डबलिंग और नई रेल लाइन परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। अश्विनी वैष्णव ने जयपुर के लिए पांच बड़ी सौगातों की घोषणा करते हुए कहा कि एमएनआईटी जयपुर में क्वॉंटम लेब, सेमिकंडक्टर लेब और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) लेब स्थापित की जाएगी।

इसके अलावा जयपुर में अत्याधुनिक एआई डेटा सेंटर और मेडिकल हब भी विकसित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं प्रदेश में निवेश, रोजगार और तकनीकी विकास के नए अवसर पैदा करेंगी तथा विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करेगी।

सतीश पूनियां, अलका सिंह और नीरज डांगी बने निर्विरोध राज्यसभा सांसद

18 जून को प्रस्तावित मतदान की नहीं पड़ी जरूरत

-कार्यालय संवाददाता- जयपुर। राजस्थान से राज्यसभा द्वितीय निर्वाचन-2026 के तहत तीनों प्रत्याशी गुरुवार को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए गए। भारतीय जनता पार्टी के डॉ. सतीश पूनिया और डॉ. अलका सिंह तथा कांग्रेस के नीरज डांगी को विधानसभा परिसर में निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।



राजस्थान से राज्यसभा की तीन सीटों पर डॉ. सतीश पूनिया, डॉ. अलका सिंह व नीरज डांगी चुने गये।

■ विधानसभा में तीनों नेताओं को निर्वाचित प्रमाण पत्र सौंपे गए

राजस्थान से राज्यसभा की तीन सीटों के लिए केवल तीन उम्मीदवार मैदान में थे, जिसके चलते मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ी। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 18 जून को मतदान होना था, लेकिन सभी प्रत्याशियों के निर्विरोध

चुने जाने से चुनाव प्रक्रिया पहले ही पूर्ण हो गई। इन सीटों का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा था, उससे पहले ही नए सदस्यों का निर्वाचन संपन्न कर लिया गया। नव निर्वाचित सांसदों का कार्यकाल जून 2032 तक रहेगा।

राजस्थान में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसदों की संख्या अब भी भाजपा और कांग्रेस के बीच बराबरी पर बनी हुई है। राजस्थान से राज्यसभा में भाजपा के मदन राठौड़,

अबकारी विभाग के पुनर्गठन और आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल के गठन से जुड़े राज्य सरकार के गत एक जून के आदेशों की क्रियाविधि पर आगामी आदेशों तक रोक लगा दी है। वहीं राज्य सरकार सहित अन्य पक्षकारों से जवाब देने के लिए कहा है। अवकाशकालीन जस्टिस चन्द्र प्रकाश श्रीमाली ने यह निर्देश राज्यसभा आबकारी सेवा संघ की याचिका पर दिया।

हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि यदि नए सेवा नियम बनाए बिना नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू होती है तो इससे उन कर्मचारियों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं, जो मौजूदा नियमों के तहत पदों पर कार्यरत हैं। कोर्ट ने यह भी माना कि ऐसी स्थिति में वरिष्ठता, पदोन्नति और भर्ती से जुड़े कई जटिल विवाद पैदा हो सकते हैं। इससे न केवल कर्मचारियों के अधिकार प्रभावित होंगे बल्कि विभाग में अनावश्यक कानूनी विवाद भी बढ़ सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में राज्यसभा चुनावों के दौरान कई मुकदमों के चलते राजनीतिक दलों को अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करनी पड़ती थी, लेकिन इस बार विधानसभा में संख्या बल के आधार पर दो सीटों पर भाजपा और एक सीट पर कांग्रेस को जीत पहले से तय मानी जा रही थी। अब राजस्थान में अगला राज्यसभा चुनाव जून 2028 में होगा, जब चार सीटों पर निर्वाचन कराया जाएगा। उस समय कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी तथा भाजपा के घनश्याम तिवारी का कार्यकाल समाप्त होगा।

बलात्कार के झूठे मुकदमे से 3 करोड़ की रंगदारी मांगी

जयपुर। जयपुर पुलिस कमिश्नरीट के दक्षिण जिले को पुलिस ने हनीट्रैप और झूठे मुकदमों के जरिए लोगों को ब्लैकमेल करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक महिला सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर बलात्कार का झूठा मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी देकर परिवारी और उसके परिवार से 3 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप है। गिरोह ने पीडित का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे बंधक बनाया और ब्लैकमेलिंग का खेल चला रखा था।

राजर्षि राज ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में रवि कुमार टांक (25) निवासी मदनबाड़ी, हरमाडा तथा एक महिला शामिल है। जांच में सामने आया कि रवि टांक ने महिला को नया मकान और रोजगार दिलाने का झांसा देकर अपने साथ मिला लिया। इसके बाद दोनों ने अन्य साथियों के साथ मिलकर हनीट्रैप की साजिश रची।

गिरोह के अन्य सदस्य दिलखुश उर्फ विलेन और अर्जुन हरिजन फिलहाल फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विशेष टीमों संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है। डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि जयपुर दक्षिण जिले में 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच जांच में 654 मामलों झूठे पाए गए हैं। इनमें से 86 मामलों में झूठी एफआईआर दर्ज कराने वाले परिवारियों के खिलाफ धारा 217/248 बीएनएस के तहत न्यायालय में प्रस्तावित पेश किए जा चुके हैं, जबकि अन्य मामलों में कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया में है।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में आज से लगेंगे 'ग्रामीण सेवा शिविर'

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिए आमजन की समस्याओं के मौके पर त्वरित समाधान के निर्देश

जयपुर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा एवं निर्देशों की अनुपालना में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन को राज्य सरकार की विभिन्न जन-कल्याणकारी एवं फ्लैगशिप योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने के लिए 12 जून से 15 जुलाई तक "ग्रामीण सेवा शिविर-2026" का आयोजन किया जाएगा। महा-अभियान के तहत राजस्व विभाग के अतिरिक्त 21 अन्य महत्वपूर्ण विभागों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। शिविरों का समय सप्ताह के कार्य दिवसों में प्रातः 9:30 बजे से सायं 6 बजे तक (अथवा कार्य समाप्त तक) रहेगा। मुख्यमंत्री शर्मा के निर्देशानुसार शिविर में आने वाले प्रत्येक नागरिक का कार्य उसी दिन पूर्ण करने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा। यदि सायं 06:00 बजे तक कुछ कार्य अपूर्ण या लंबित रहते हैं, तो विभागवार उनकी सूची संघारित की जाकर समयबद्ध रूप से निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। शिविर की शुरुआत से समाप्त तक सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी।

■ 22 प्रमुख विभागों की सहभागिता से नागरिकों को मौके पर ही मिलेगा योजनाओं का लाभ

■ प्रातः 9:30 से सायं 6 बजे तक रहेगा समय, लंबित कार्यों का समयबद्ध निस्तारण होगा सुनिश्चित

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग मातृ-शिशु स्वास्थ्य जांच, कैसर एवं सिकल सेल स्क्रीनिंग, टीबी जांच, टीकाकरण तथा आधुनिक भारत कार्ड वितरण करेगा। पशुपालन विभाग द्वारा पशु स्वास्थ्य शिविर, टीकाकरण एवं मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत बीमा पॉलिसियां वितरित की जाएगी। ग्रामीण सेवा शिविर में ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युत सप्लाई ट्रांसफार्मर एवं बिजली संबंधी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। जबकि कृषि विभाग किसानों को विभिन्न योजनाओं एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी उपलब्ध कराएगा। आयोजना विभाग जनघन खाते, सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाओं, अटल पेंशन योजना एवं जनआधार से जुड़े कार्य करेगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग एनएफएसए से संबंधित लंबित प्रकरणों, ई-केवाईसी एवं आधार सौंदींग का निस्तारण करेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पेंशन सत्यापन, पेंशन हार योजना, यूडीआईडी कार्ड, कृत्रिम अंग वितरण एवं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से संबंधित कार्य किए जाएंगे। शिविरों में महिला एवं बाल विकास विभाग लाडो प्रोत्साहन योजना, काली बाई भील सम्बल उद्दान योजना, पन्नाया सुरक्षा एवं समान केन्द्र, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना, वन स्टॉप सेन्टर, महिला हेल्पलाइन, शिक्षा सेतु, मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजनाओं का लाभ प्राप्त महिलाओं तक पहुंचाएगा।

जवाब मांगा

जयपुर। हाईकोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारी के तौर पर कार्यरत रहे कर्मचारी को दिवंगत वेतनमान और ग्रेड पे परिलमा की वसूली करने पर प्रमुख पंचायती राज सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कोटा और पेंशन निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपिट ने यह आदेश प्रेम प्रकाश नागर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि यदि नए सेवा नियम बनाए बिना नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू होती है तो इससे उन कर्मचारियों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं, जो मौजूदा नियमों के तहत पदों पर कार्यरत हैं। कोर्ट ने यह भी माना कि ऐसी स्थिति में वरिष्ठता, पदोन्नति और भर्ती से जुड़े कई जटिल विवाद पैदा हो सकते हैं। इससे न केवल कर्मचारियों के अधिकार प्रभावित होंगे बल्कि विभाग में अनावश्यक कानूनी विवाद भी बढ़ सकते हैं।

फर्जी एम.टेक. डिग्री लगाकर सरकारी नौकरी पाने वाला जलदाय विभाग का जेईएन दुर्गाशंकर मेनारिया गिरफ्तार

आरोपित ने आरपीएससी भर्ती में स्वयं को अधिक योग्य दिखाने के लिए एम.टेक. की कूटरचित डिग्री प्रस्तुत की थी



दुर्गाशंकर मेनारिया

तहसील के वाना गांव का निवासी है। वह वर्तमान में जलदाय विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर भीण्डर क्षेत्र में कार्यरत है। जांच में सामने आया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी), अजमेर द्वारा वर्ष 2018-19 में समूह अनुदेशक, सर्वेयर एवं सहायक शिक्षिता सलाहकार ग्रेड-द्वितीय भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। इस भर्ती के लिए एम.टेक. स्नातक की योग्यता निर्धारित थी, लेकिन आरोपी ने स्वयं को अधिक योग्य साबित करने के उद्देश्य से अपने ऑनलाइन आवेदन के साथ मानव भारतीय विश्वविद्यालय, सोलन (हिमाचल प्रदेश) से वर्ष 2010 से 2012 के दौरान प्राप्त एम.टेक. (इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम) की डिग्री

में सहायक तकनीकी अधिकारी के रूप में नौकरी की थी। वहां से प्राप्त अनुभव प्रमाण पत्र का उपयोग भी उसने अपनी योग्यता और अनुभव दर्शाने के लिए किया था। एम.टेक. डिग्री की कमी के कारण ही नौकरी नहीं की गई। जांच में डिग्री पूरी तरह फर्जी और कूटरचित पाई गई। इसके बाद प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के निदेशक ने एसओजी थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसओजी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एसओजी की पूछताछ में यह भी सामने आया कि आरोपी ने इसी कथित एम.टेक. डिग्री के आधार पर वर्ष 2015 से 2020 तक सिरौही जिले के पिंडवाडा स्थित माधव विश्वविद्यालय

मुख्यमंत्री भजनलाल ने विकसित राजस्थान-2047 का रोड मैप नीति आयोग में प्रस्तुत किया

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की 21वीं परिषद की बैठक में उन्होंने भाग लिया

नई दिल्ली/जयपुर, 11 जून। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक में शामिल हुए। उन्होंने राजस्थान के विकास के विजन, उपलब्धियों एवं भावी कार्ययोजना को प्रस्तुत करते हुए कहा कि राजस्थान विकसित भारत-2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की संशा के अनुरूप, राज्य सरकार गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को राज्य सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के केंद्र में रखकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की विकास का प्रमुख आधार बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की।

के अंतर्गत 2 करोड़ 19 लाख बीमा पॉलिसियां जारी की गई हैं तथा पीएम-कुसुम योजना (कम्पोनेंट-ए) के तहत 723 मेगावाट क्षमता की 496 सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित

की गई हैं। इन दोनों क्षेत्रों में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। उन्होंने बताया कि नीति आयोग की वर्ष 2025-26 की तृतीय तिमाही रैंकिंग में नीमराना ब्लॉक ने

■ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के युवाओं की शक्ति के उपयोग के मंत्र को आत्मसात करते हुए राज्य सरकार प्रदेश की 63 प्रतिशत युवा आबादी को विकास का मुख्य आधार बना रही है।

राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, जबकि दोसा जिले के रामगढ़ पंचवारा तथा जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ ब्लॉक ने विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर तक जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए ग्राम विकास रथ भिजवाए गए।

मीनाक्षी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दिया गया कि नटराज का नामांकन खारिज कर दिया गया, जबकि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं था, जिसे चुनाव कानून के तहत उजागर करना आवश्यक था। चुनाव आयोग द्वारा अपने कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श के बाद जल्द ही निर्णय लेने की उम्मीद है। नटराज मध्य प्रदेश से कांग्रेस की एकमात्र राज्यसभा उम्मीदवार थीं, और उनके नामांकन खारिज होने के कारण पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी अब कोई दूसरा उम्मीदवार खड़ा कर नहीं सकती, क्योंकि नटराज का पचा नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून के बाद खारिज किया गया। यह विवाद 2022 में तेलंगाना के एक मामले से उत्पन्न हुआ, जिसमें एक महिला ने एक कांग्रेस नेता पर उत्पीड़न और धमकियों का आरोप लगाया था। महिला ने दावा किया कि शिकायत के बावजूद, कांग्रेस नेतृत्व ने रेड्डी के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्होंने यह मामला उस समय कांग्रेस संगठन से छुड़ी मीनाक्षी नटराज के सामने भी उठाया था। कांग्रेस का तर्क है कि नटराज किसी एफआईआर में आरोपी नहीं थीं और उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं था। इसलिए पार्टी का कहना है कि नामांकन हलफनामे में इस मामले का उल्लेख करने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं थी। मध्य प्रदेश से भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवार महेश केवट का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में चल रहा है।

अशोक गहलोत का जैसा लगाव वैभव के साथ है, वैसा ही मेरे से है - पायलट

राजेश पायलट की 26वीं पुण्यतिथि पर सचिन ने गहलोत को मोहब्बत का पैगाम दिया

दौसा 11 जून (निर्स)। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने गुरुवार को भंडाना में किसान नेता राजेश पायलट की 26 वीं पुण्यतिथि पर राजेश पायलट स्मारक पर हजारों लोगों की मौजूदगी में

■ इस भावुक अवसर पर स्व. राजेश पायलट की पत्नी रमा पायलट तथा सचिन पायलट के दोनों पुत्र आरान और विहान भी उपस्थित थे।



पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने गुरुवार को भंडाना में किसान नेता राजेश पायलट की 26 वीं पुण्यतिथि पर राजेश पायलट स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की।

पुष्पांजलि अर्पित की। सचिन पायलट जयपुर से अपने काफिले के साथ सभा स्थल पर साढ़े दस बजे पहुंचे।

इस मौके पर कांग्रेस के महासचिव व पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा हाल ही में मानेसर प्रकरण को दोबारा हवा दिए जाने के स्वागत पर कहा कि अशोक गहलोत का जैसा लगाव और स्नेह अपने पुत्र वैभव गहलोत के साथ है, वैसा ही स्नेह और आशीर्वाद मेरे साथ भी है।

उन्होंने कहा कि आज देश के सामने गंभीर चुनौतियां हैं। पायलट ने नीट परीक्षा सहित देश में लगातार हो रही दर्जनों परीक्षाओं के पेपर लीक मामलों पर गहरी चिंता व्यक्त की। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं सहित, समाज के विभिन्न वर्गों से आए हजारों लोगों ने पायलट को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ और उपस्थित जनसमूह ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस भावुक क्षण में राजेश पायलट

की पत्नी रमा पायलट और उनके पुत्र व पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट मौजूद रहे। साथ ही, सचिन पायलट के दोनों बेटे आरान और विहान भी दादा की पुण्यतिथि पर विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में राजस्थान कांग्रेस के कई वर्तमान व पूर्व मंत्रियों, सांसदों और विधायकों ने शिरकत की। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री बीडी कल्ला, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खारियावास, जितेन्द्र सिंह, ममता भूपेश, हेमराम चौधरी और जायदा खान मौजूद थे। इनके अलावा, दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा, सांसद भजनलाल जाटव, सांसद संजना जाटव, बस्ती विधायक लक्ष्मण मीणा, पूर्व विधायक रमेश मीणा, पाली विधायक भीमराज भाटी, अमीन कागजी, सुरेश मोदी, विधायक मुकेश भाकर, दौसा विधायक दीनदयाल

बैरवा, पूर्व विधायक वेदप्रकाश सोलंकी, धीरज गुर्जर, प्रशांत बैरवा, इंद्राज गुर्जर, निहारिका जोरवाल, जिला कांग्रेस कमिटी अध्यक्ष रामजीलाल ओड , पूर्व विधायक जीआर खटाना, संदीप शर्मा, जिला प्रमुख हीरालाल सैनी, जिला प्रवक्ता मुकेश राणा सहित सैकड़ों पार्टी पदाधिकारी प्रधान एवं हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

'कर्नाटक...

बढ़कर 2,400 रुपये प्रति टन हो गई है। जो लगभग 950 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि पुरानी कचरा प्रबंधन व्यवस्था पर 30 वर्षों में लगभग 6,117 करोड़ रुपये का खर्च आता, जबकि नए अनुबंध के तहत अनुमानित लागत 39,000 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है।

म.प्र. से भाजपा ...

राज्यसभा की तीन सीटों का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है। इनमें दो सीटें भाजपा और एक सीट कांग्रेस के खाते की है। इन तीनों रिक्त होने वाली सीटों पर द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए भाजपा के तीन उम्मीदवार-तरुण चुग, महेश केवट और रजनीश

अग्रवाल तथा कांग्रेस की मीनाक्षी नटराज ने नामांकन दाखिल किया था, लेकिन भाजपा की आपत्ति के बाद हलफनामे में अनियमितताएं पाए जाने के आधार पर कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराज का नामांकन गत मंगलवार को खारिज कर दिया गया था।

अभिषेक बनर्जी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उन्होंने ऐसी कोई अनुमति नहीं दी थी। आरोप है कि विधायकों के हस्ताक्षर जाली हैं। यह एक गंभीर आरोप है और यदि यह साबित हो जाता है तो सात वर्ष तक की जेल की सजा हो सकती है। अभिषेक को चारों ओर से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और उनके खिलाफ विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है।

इस समय पार्टी के भीतर से यह आवाज तेज हो रही है कि अभिषेक बनर्जी पार्टी का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। आज पार्टी के वरिष्ठ नेता और अनुभवी राजनेता कल्याण बनर्जी, जो अब तक ममता बनर्जी के सबसे वफादार समर्थकों में गिने जाते थे, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है। कल्याण बनर्जी ने कहा कि या तो अभिषेक बनर्जी पार्टी के

नेता बने रहेंगे और वे बाहर हो जाएंगे, अर्थात् ममता बनर्जी को पार्टी में अभिषेक की स्थिति पर निर्णय लेना होगा और उन पुराने वफादार नेताओं के पक्ष में फैसला करना होगा, जिन्होंने वर्षों तक उनके साथ काम किया है। पहले ही 80 निर्वाचित विधायकों में से 64 विधायक पार्टी नेतृत्व की बात मानने से इनकार कर चुके हैं और वे सभी ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व में एकजुट हो गए हैं। इन विधायकों ने ऋतब्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नामित किया है। कहा जा रहा है कि और विधायक भी उनके साथ जुड़ सकते हैं। दूसरी ओर, राज्यसभा में पार्टी के एक और सदस्य ने इस्तीफा दे दिया है, जिससे पार्टी के सदस्यों की संख्या घटकर 10 रह गई है। सांसदों और विधायकों की संख्या बहुत कम हो जाने के कारण पार्टी की राजनीतिक हैसियत लगभग नगण्य रह गई है।

चुनावी हार के बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई है। ममता बनर्जी, जिन्हें पहले राष्ट्रीय राजनीति में विशेष महत्व दिया जाता था, अब मुलाकातों के लिए इंतजार करने को मजबूर बताई जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि विभिन्न राष्ट्रीय नेताओं को किए गए उनके फोन कॉल का भी जवाब नहीं दिया रहा है। भारतीय राजनीति की सबसे तूफानी नेता ममता बनर्जी के पास दो ही विकल्प हैं, या तो खम हो जाएं या हारिए पर चली जाएं। उन्हें अब याचक जैसी भूमिका का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व में, जब भी वे दिल्ली से लौटती थीं तो राष्ट्रीय राजनीति के मुद्दों पर खुलकर टिप्पणी करती थीं, लेकिन कल कोलकाता हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। अब उनकी हालत ऐसी हो गई है कि उन्हें नौकरी की तलाश में आवेदन करना पड़ रहा है।

पिछले दो दिनों में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने क्रमशः सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कई बार मुलाकात की। बताया जा रहा है कि उन्हें अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने का प्रस्ताव दिया गया है। कहा जा रहा है कि ममता और अभिषेक को अखिल भारतीय स्तर पर कुछ पद देने का आश्वासन दिया गया है। लेकिन उनसे यह भी कहा गया है कि वे अपनी पार्टी का पूरी तरह कांग्रेस में विलय कर दें और अलग राजनीतिक दल के रूप में तृणमूल कांग्रेस को भूल जाएं। यह प्रस्ताव कांग्रेस के लिए भी आकर्षक हो सकता है। ममता और अभिषेक की राजनीतिक प्रासंगिकता काफी घट चुकी है। वे अपना जनाधार खो चुके हैं और राज्य विधानसभा तथा संसद, दोनों में विधायकों और सांसदों पर उनका नियंत्रण समाप्त हो गया है। हालांकि पार्टी

के पास अभी भी भारी मात्रा में धनराशि मौजूद है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, तृणमूल कांग्रेस के पास लगभग 3,000 करोड़ रुपये का राजनीतिक कोष है। चुनावी बॉन्ड से प्राप्त चंटे में भाजपा के बाद और कांग्रेस से आगे, तृणमूल कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही थी। अब पार्टी नेताओं को इस खजाने के असली हकदार के तौर पर अपनी वैधता साबित करनी होगी। अब तक पार्टी की धनराशि का नियंत्रण शीर्ष दो पदाधिकारियों, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के पास था। लेकिन अब, जब अधिकांश विधायक और सांसद एकजुट होकर स्वयं को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस बता रहे हैं, तो इस धनराशि पर नियंत्रण का प्रश्न बड़ा विवाद बन सकता है। पार्टी फंड पर अधिकार को लेकर भविष्य में गंभीर संघर्ष होने की संभावना जताई जा रही है।




गाड़ी बेचें भरोसे के साथ, सिर्फ TRUE VALUE पर






आज ही अपने नज़दीकी ट्रू वैल्यू डीलरशिप पर जाएँ।



फ्री-होम डेवैल्यूएशन



आसान RC ट्रान्सफर



ऑन-टाइम पेमेंट

True Value ऐप यहाँ डाउनलोड करें।

पूछताछ के लिए कॉल करें 1800 102 1800 | या जाएँ यहाँ www.marutisuzukitruevalue.com



JODHPUR: OPPOSITE SARAN NAGAR GATE A, BANAR ROAD, JODHPUR, LMJ SERVICES: 7230078225, 8094011141 | PLOT NO. C 62, MARUDHARA INDUSTRIAL AREA, BASNI 1ST PHASE SARASWATI NAGAR, JODHPUR, AURIC MOTORS PVT. LTD.: 7230043141, 7230043140 | BASNI: 32-A, HEAVY INDUSTRIAL AREA, NEAR F.C.I. GODOWNS, JODHPUR, SHRI KRISHNA AUTO SALES: 9799998584, 9829197669 | PALI: NEAR VEER PRABHU GARDEN, JODHPUR ROAD, PALI, LMJ SERVICES: 7230026924.

*नियम एवं शर्तें लागू। विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया निकटतम डीलरशिप पर संपर्क करें। दर्शाई गई छवियाँ केवल प्रतिनिधिक उद्देश्य के लिए हैं। वाहन पर काला शीशा प्रभाव के कारण होता है।